संपादकीय

प्रिय पाठको! आपको *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* का एक साल (29 जुलाई, 2021) पूरा होने पर बधाई! कोविड-19 महामारी के संकट काल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए अध्यापकों, प्रशासकों, नीति-निर्माताओं, अभिभावकों एवं अन्य हितधारकों को उनके द्वारा की गई कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। इस महामारी के कारण शिक्षा में आए बदलावों के अंतर्गत, विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण ही अब सामान्य शिक्षण का रूप ले चुका है, जिनमें ई-पाठशाला, एन.आर.ओ.ई.आर., *पीएम ई-विद्या चैनल, दीक्षा, निष्ठा एवं स्वयं* जैसे पोर्टल एवं एप महत्वपूर्ण हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 202*0 का एक साल पूरा होने पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की गई। जिनमें 'विद्या प्रवेश कार्यक्रम', 'निष्ठा 2.0', 'सफल' (बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का सुव्यवस्थित तरीके से विश्लेषण और आकलन), राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण संरचना (एन.डी.ई.ए.आर.) और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फ़ोरम (एन.ई.टी.एफ.) का शुभारंभ किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषाओं के महत्व पर ज़ोर दिया गया है ताकि विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा हो। साथ ही भारतीय सांकेतिक भाषा को पहली बार भाषा विषय का दर्जा दिया गया है। इससे भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा मिलेगा और दिव्यांगजनों को मदद मिलेगी।

यह अंक भी *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के इन्हीं सरोकारों के विविध रूपों को प्रस्तुत करता है, जिनमें शोध पत्र, 'माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति का अध्ययन' प्रस्तुत किया गया है। अध्यापकों की पेशेवर आचार नीति एक मार्गदर्शक की तरह है।

हमारे अनुभवों का जीवन में विशेष महत्व होता है। अनुभव आधारित अधिगम स्थायी, व्यावहारिक और कभी न भूलने वाला होता है। लेख '*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* और अनुभव आधारित अधिगम' इन सभी सरोकारों पर चर्चा करता है और शिक्षा जगत से जुड़े सभी सेवाकालीन शिक्षकों और सेवा-पूर्व शिक्षकों और विद्यार्थियों में अनुभव आधारित अधिगम की महत्ता के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करता है।

आनुभविक अधिगम युक्तियों के लिए विद्यार्थियों के दैनिक जीवन के अनुभवों, विचारों और मतों आदि को कक्षा में शामिल करना आवश्यक होता है। इस आधारभूत मान्यता के सापेक्ष शोध पत्र 'सामाजिक विज्ञान के शिक्षण-अधिगम में आनुभविक अधिगम' में यह विवेचना की गई है कि सामाजिक विज्ञान अध्यापक विद्यार्थियों के किन अनुभवों को और कैसे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सम्मिलित करते हैं?

भारत एक बहुभाषी देश है, जिसमें विविध संस्कृतियाँ एवं भाषाएँ विद्यमान हैं। राष्ट्र की धरोहर को सहजने एवं शिक्षण-अधिगम में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। लेख 'विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण-अधिगम की बुनियाद— मातृभाषा' शिक्षा के माध्यम 'मातृभाषा' की एक समालोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमें प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी है। जिसमें तकनीकी का समुचित प्रयोग भी करना है, लेकिन तकनीकी के उपयोग के बारे में कई दुविधाएँ और संदेह हैं। इन्हीं तकनीकी से जुड़े सरोकारों पर केंद्रित लेख 'पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में टेक्नालॉजी का सार्थक प्रयोग' दिया गया है।

हस्त एवं लोक कला को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से जोड़ने और उनसे संबंधित गतिविधियों को कक्षा में प्रस्तुत करने पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में विशेष बल दिया गया है। लेख 'सामाजिक विज्ञान के शिक्षण-अधिगम में स्थानीय हुनरों का समावेशन' में उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत, इतिहास (*हमारे अतीत*) की पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु में उपयुक्त हुनर की खोज कर उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं।

शिक्षा में की गई प्रत्येक पहल एवं परिवर्तन के सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। लेख 'विद्यालयी शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण-अधिगम— बदलाव की एक पहल' में इन्हीं पहलुओं पर चर्चा की गई है।

शोध पत्र 'विद्यालयी शिक्षा में शिक्षण का ऑनलाइन मॉडल— चुनौतियाँ एवं सुझाव' में यह पाया गया कि शिक्षण की विधियों और तरीकों; पाठ योजनाओं; कक्षा की विभिन्न प्रक्रियाओं, जैसे— चर्चा, समूह कार्य, गतिविधियों आदि से जुड़ी कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें नेटवर्क कनेक्टिविटी, समय का सही उपयोग, बच्चों की सहभागिता, लोकतांत्रिकता, बेहतर शिक्षण-अधिगम आदि प्रमुख हैं। इस शोध पत्र के अंतिम भाग में महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं, जो शिक्षा के ऑनलाइन मॉडल की समस्याओं को दूर करने में सहायक हो सकते हैं।

'कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन माध्यम से प्रारंभिक स्तर की कक्षाओं हेतु अकादमिक प्रयासों का अध्ययन' नामक शोध पत्र में बताया गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण दूरस्थ अंचल, वन ग्राम व ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की अकादमिक गतिविधियाँ नगण्य हो गईं, जो भविष्य के लिए चिंताजनक हैं।

लेख '*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के परिप्रेक्ष्य में अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु उपाय— एक प्रयास' में अध्यापक शिक्षा में सुधार हेतु कुछ उपायों की चर्चा की गई है, जिससे भारत के भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अध्यापक तैयार किए जा सकें।

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु प्रोत्साहन के लिए आकलन— परफ़ॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, केंद्र प्रायोजित महत्वपूर्ण योजना 'समग्र शिक्षा' की एक पहल है। इसी पहल के आधार पर लेख 'परफ़ॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के आधार पर *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* के संदर्भ में स्कूली अध्यापकों की चुनौतियों का विश्लेषण तथा सार्थक सुझाव' प्रस्तुत किया गया है।

वहीं लेख 'विद्यालयी शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्य एवं अध्यापकों की भूमिका' में विद्यार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास व संवर्द्धन में अध्यापकों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई है।

जबकि शोध पत्र 'जनजातियों के विकास की शासकीय योजनाओं के प्रति सहरिया जनजाति की जागरूकता एवं उन पर इन योजनाओं का प्रभाव' का मुख्य उद्देश्य सहरिया जनजाति के शैक्षणिक विकास के

संदर्भ में जनजातियों के शैक्षणिक विकास से संबंधित संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना है।

आप सभी की प्रतिक्रियाओं की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। आप हमें लिखें कि यह अंक आपको कैसा लगा। साथ ही, आशा करते हैं कि आप हमें अपने अनुभव आधारित मौलिक तथा प्रभावी लेख, शोध पत्र, आलोचनात्मक समीक्षाएँ, श्रेष्ठ अभ्यास, पुस्तक समीक्षाएँ, नवाचारी प्रयोग, क्षेत्र (फ़ील्ड) अनुभव आदि प्रकाशन हेतु आगे दिए गए पते पर प्रेषित करेंगे।

अकादमिक संपादकीय समिति